

अनाधिकृत नरिमाणों को ध्वस्त करने हेतु नए नयिम चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाधिकृत नरिमाणों को ध्वस्त करने से पहले एजेंसियों के लयि दशिश-नरिदेश जारी कयि हैं ।

- ध्वस्तीकरण को अंतमि रूप देने से पहले नोटसि अवश्य दयिा जाना चाहयि तथा वयक्तगित सुनवाई का अवसर भी प्रदान कयिा जाना चाहयि ।

मुख्य बढि

- ध्वस्तीकरण के नये नयिम:

- अनविर्य कारण बताओ सूचना एवं प्रतीक्षा अवधः
 - कारण बताओ सूचना जारी कयि बना कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य नहीं कयिा जाना चाहयि ।
 - एजेंसियों को ध्वस्तीकरण का आदेश देने से पहले नोटसि प्राप्त की तारीख से **15 दनि तक प्रतीक्षा करनी होगी** । नयिम अपील का अवसर प्रदान करते हैं, अंतमि आदेश के बाद **15 दनि** के लयि ध्वस्तीकरण में देरी होनी चाहयि ।
 - मालकों/कब्जेदारों को अनाधिकृत संरचनाओं को स्वयं हटाने या ध्वस्त करने के लयि **15 दनि का समय** दयिा जाना चाहयि ।
- पारदर्शति उपायः
 - नोटसि, उत्तर और आदेश सहति सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण करने के लयि तीन महीने के भीतर एक [डजिटल पोर्टल](#) स्थापति कयिा जाना चाहयि ।
 - **नोटसि ज़लि मजसिस्ट्रेट (DM)** कार्यालय को ईमेल के माध्यम से स्वचालति पावती के साथ भेजे जाने चाहयि ।
 - वयक्तगित सुनवाई के वविरण अवश्य दर्ज कयि जाने चाहयि ।
- वधिवंस आदेश एवं अनुपालनः
 - अंतमि आदेश में नमिनलखिति का उल्लेख होना चाहयि:
 - क्या संरचना **समझौता योग्य** है (शुलक देकर नयिमति कयिा जा सकता है) ।
 - **अनाधिकृत/गैर-शमनीय** भागों का वविरण ।
 - वधिवंस क्यों आवश्यक है?
 - इन नयिमों का पालन न करने पर अधिकारियों के वरिद्ध **अवमानना कार्यवाही** और **अभयिोजन चलाया जा सकता है** ।
- कानूनी एवं प्रशासनकि टपिणयिः
 - नये नयिमों में कई कदम पहले से ही वभिन्न अधनयिमों के अंतर्गत मौजूद हैं ।
 - नई सुवधाओं का उद्देश्य ध्वस्तीकरण में **पारदर्शति और स्थरिति में सुधार लाना** है ।
 - ज़ल्दबाजी में कयि गए ध्वस्तीकरण और पुराने ध्वस्तीकरण आदेशों के लंबति रहने के कारण कदाचार और अनाधिकृत नरिमाण को बढावा मलिता है ।
 - नगर नगिम के अधिकारियों ने अनुपालन की पुष्टि की और स्पष्ट कयिा कि अस्थायी अतकिरणों से **उत्तर प्रदेश नगर नगिम अधनयिम, 1959** के तहत नपिटा जाएगा ।